संख्या:81/2022/222/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 मार्च, 2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य के मद के नाम में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में शासनादेश संख्या-76/2022/217/35-4-2022 दिनांक 10 मार्च,2022 द्वारा अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण से सम्बंधित 02 कार्यों की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश के लेखाशीर्ष को निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

"अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0304-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/ पुस्तकालय/ बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता/ वादकारी के लिये स्थायी □ांचे के चालू कार्य के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य"

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:81/2022/222(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in